*आधुनिक वित्तीय प्रणाली में लेखापरीक्षा की भूमिका**

शक्तिकांत दास

मुझे आज यहां भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (आईएएएस) के परिवीक्षाधीनों और अन्य अधिकारियों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी (एनएएए), शिमला में आकर बहुत खुशी हो रही है। परिवीक्षाधीनों के लिए, यह एक ऐसा समय है जब वे सार्वजनिक वित्त और शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता के प्रमुख ध्वजवाहक के रूप में राष्ट्र की सेवा में यात्रा शुरू कर रहे हैं।

किसी भी देश की समग्र प्रगति में सिविल सर्विसेज की अहम भूमिका होती है। वे हमारे देश के विकास और विकास में अंतर्निहित स्टील फ्रेम हैं। सिविल सेवाओं के भीतर, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा संघ और राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के खातों की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। यह राज्य सरकारों के खातों के रखरखाव और लेखा परीक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। सार्वजनिक व्यय के लिए जवाबदेही ढांचे को संचालित करके शासन और पारदर्शिता में सुधार लाने में लेखापरीक्षा तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।

विश्व स्तर पर एकीकृत अर्थव्यवस्था में, निष्पक्ष और निष्पक्ष ऑडिट न केवल एक घरेलू चिंता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर हमारी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को बढ़ाने का एक साधन भी है। यह कठिन समय, जैसे कि हम अभी कोविड-19 महामारी के कारण गुजर रहे हैं, के दौरान अधिक महत्व रखता है। वित्तीय बाजारों की बढ़ती जटिलता और कुशल संसाधन आवंटन के बारे में जनता से उच्च उम्मीदों के साथ, लेखा परीक्षा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि भारत तेजी से बढ़ने की इच्छा रखता है, सभी हितधारकों को वित्तीय प्रदर्शन पर अधिक आश्वासन प्रदान करने के लिए लेखा परीक्षकों की विशेषज्ञता और स्वतंत्रता का लाभ उठाना होगा। हमें एक गतिशील और लचीली अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत लेखा परीक्षा की जरूरत है।

इसलिए, मैंने आज अपने संबोधन के लिए आधुनिक वित्तीय प्रणाली में लेखा परीक्षा की भूमिका का विषय चुना है। मैं निम्न से संबन्धित विषयों पर चर्चा करूंगा, लेखापरीक्षा की भूमिका और इसके महत्व से संबंधित क्षेत्रों; एक संस्था के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की भूमिका; वित्तीय क्षेत्र में एक नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में लेखा परीक्षा के साथ आरबीआई का अनुभव; लेखापरीक्षा विफलताएं क्यों होती हैं और उनका प्रभाव; आधुनिक लेखापरीक्षा उपकरणों को अपनाना; और लेखापरीक्षा की बदलती प्रकृति।

लेखापरीक्षा की उत्पत्ति

लेखापरीक्षा व्यवसाय की प्रारंभिक उत्पत्ति मध्यकालीन यूरोप में देखी जा सकती है। ब्रिटिश राजकोष द्वारा बनाए गए पाइप रोल्स (वित्तीय अभिलेखों का संग्रह) राजशाही के खातों की लेखा परीक्षा प्रक्रिया के कुछ शुरुआती लिखित वित्तीय रिकॉर्ड थे। यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय अभिलेखागार में सबसे पुराना जीवित पाइप रोल वित्तीय वर्ष 1129-11301 को कवर करता है । तब से, यह पेशा मुक्त बाजारों की प्रतिस्पर्धी गतिशीलता से व्यवस्थित रूप से विकसित हुआ। हालाँकि, 19वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड और अमेरिका में सीमित देयता कंपनियों के विकास ने पेशेवर लेखाकारों और लेखा परीक्षकों की मांग पैदा की। ऐसी सीमित देयता कंपनियों, विशेष रूप से रेलवे कंपनियों, से उत्पन्न दिवालिया और घोटालों से प्रेरित, अंग्रेजी कंपनी अधिनियम, 1845 में पहली बार शेयरधारकों से बनी एक ऑडिट समिति द्वारा कुछ कंपनियों के खातों की अर्ध-वार्षिक ऑडिट की आवश्यकता अपेक्षित की गई [2]।

---

* श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक का सम्बोधन - 25 अक्टूबर, 2021 - नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स (एनएएए), शिमला में।

[1] https://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/medieval-financial-records-pipe-rolls-1130-1300/

[2] ऑडिट फर्मों और नेटवर्क को विनियमित करने पर विशेषज्ञों की समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों पर रिपोर्ट, अक्टूबर 2018, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय

भारतीय संदर्भ में, लेखा और लेखा परीक्षा का इतिहास बहुत लंबा है। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में सार्वजनिक वित्त के लेखा और लेखा परीक्षा पर विस्तृत नियम निर्धारित किए गए थे। अर्थशास्त्र में ".....सभी प्रकार के राजस्व का संग्रह और लेखा-परीक्षा" का उल्लेख है और आगे कहा गया है कि "..... आषाढ़ के महीने में लेखा प्रस्तुत किया जाएगा ..... वे लेखाकार जो समय पर खुद को प्रस्तुत नहीं करते हैं या शुद्ध राजस्व के साथ अपनी खाता बही प्रस्तुत न करें, उनसे देय राशि का दस गुना जुर्माना लगाया जाएगा[3]।

बहुत बाद के इतिहास में, 1858 में महालेखाकार का कार्यालय स्थापित किया गया था, जो बाद में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय बन गया। जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है, यूरोप में विकास के बाद, भारतीय कंपनी अधिनियम 1866, ने संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए एक वर्ष में कम से कम एक बार, एक लेखा परीक्षक द्वारा अपने खातों का सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया।

लेखापरीक्षा की भूमिका और महत्व

जैसा कि आप जानते होंगे, लेखा परीक्षा को एक उद्यम के खातों और अभिलेखों की एक परीक्षा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट ठीक से तैयार की गई है ताकि यह एक व्यापार के मामलों की वित्तीय स्थिति सही और निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित करे। लेखापरीक्षा की आवश्यकता पर विचार करने के लिए, हमें यह समझना होगा कि उपलब्ध साक्ष्यों और सूचनाओं के आधार पर आर्थिक निर्णय तेजी से किए जा रहे हैं।

गलत जानकारी से उपेष्टतम निर्णय या अतिरिक्त संसाधन आबंटन हो सकता है, जो न तो सार्वजनिक हित में होगा जहां एक सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल है, न ही व्यक्तिगत हितधारकों के हित में। बैंकिंग क्षेत्र से एक उदाहरण देने के लिए, यदि कोई बैंक गलत और भ्रामक वित्तीय विवरणों के आधार पर ऋण स्वीकृत करता है और उधारकर्ता कंपनी अंततः चुकाने में असमर्थ होती है, तो बैंक मूलधन और ब्याज दोनों को खो देता है। नुकसान के अलावा, यह बैंक को जोखिम से बचा सकता है और अन्य योग्य कंपनियों को बैंक फंडिंग से वंचित कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, बैंक अन्य उधारकर्ताओं से उच्च ब्याज दर वसूल कर इस नुकसान की भरपाई करने का प्रयास कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे उधारकर्ताओं में गैर-व्यवहार्यता के बीज बोने के अलावा, समाज के लिए उच्च ब्याज लागत की स्थिति पैदा होती है। अंतत: दांव पर जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा होगी।

अविश्वसनीय जानकारी की समस्या को दूर करने के लिए, एक आश्वासन तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, जो निर्णय लेने वालों को उन्हें प्रदान की जा रही जानकारी की गुणवत्ता और सटीकता के बारे में स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करता है। ऐसा तंत्र आंतरिक और बाह्य दोनों, लेखापरीक्षा तंत्र के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

सूचनात्मक, सटीक, विश्वसनीय और विश्लेषणात्मक ऑडिट रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता और विकास दोनों के लिए अनिवार्य हैं। लेखा परीक्षकों की प्राथमिक भूमिका एजेंसी की समस्याओं को हल करना है। एजेंट (प्रबंधन या सरकारी विभाग/सार्वजनिक निधि के उपयोगकर्ता) और प्रिंसिपल (शेयरधारक, निवेशक और जनता) के बीच सूचना विषमता के कारण एजेंसी की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एजेंसी की समस्याओं को हल करने के लिए, सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में से एक है लेखा परीक्षकों को द्वारपाल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करना, चाहे वह पूंजी बाजार के लिए हो या सार्वजनिक धन के लिए। इस प्रकार, लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और लेखा परीक्षा के पेशे में नैतिकता की भूमिका दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के मामले में, लेखा परीक्षा सुशासन की आधारशिला है। निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रदान करके कि क्या सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन जिम्मेदारी से और प्रभावी ढंग से इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है, एक निष्पक्ष लेखा परीक्षा नागरिकों और हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करता है। जैसा कि वे कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में बेहतर निरीक्षण, अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता की सुविधा होनी चाहिए। 'निगरानी' से पता चलता है कि क्या

[3] कौटिल्य का अर्थशास्त्र आर. शामाशास्त्री द्वारा अंग्रेजी में अनूदित

सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं वह कर रही हैं जो उन्हें नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार करना चाहिए। 'अंतर्दृष्टि' सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रमों, नीतियों, संचालन और परिणामों का एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करके निर्णय लेने वालों की सहायता करती है। 'दूरदर्शिता' प्रवृत्तियों और उभरती चुनौतियों की पहचान करती है। लेखापरीक्षक इनमें से प्रत्येक भूमिका को पूरा करने के लिए वित्तीय लेखा परीक्षा, प्रदर्शन लेखा परीक्षा और सलाहकार सेवाओं जैसे उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं।[4]

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की संस्था की भूमिका और महत्व

हमारे जैसे प्रतिनिधि लोकतंत्र में, सार्वजनिक संस्थान नागरिकों के हितों की सेवा के लिए कार्य करते हैं, जिसके द्वारा सार्वजनिक निधियों का "सर्वहित" के लिए व्यय या निवेश किया जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) देश के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के रूप में एक ओर नागरिकों और संसद के मध्य और दूसरी ओर सार्वजनिक संस्थानों/ विभागों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावहारिक आचरण और परिचालनों की नियमित और स्वतंत्र परीक्षा के साथ-साथ समीक्षा के अधीन होता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ सार्वजनिक संस्थानों के वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखा परीक्षा के माध्यम से सीएजी की लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, मुख्य रूप से देश में करदाताओं से प्राप्त सार्वजनिक निधियों के उपयोग के लिए जवाबदेही और वैधता के स्तर को बढ़ाती हैं। सीएजी द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के आधार पर सार्वजनिक निधियों के आबंटन पर भविष्य में निर्णय, पथ-परिवर्तन के लिए कार्यान्वयन अंतराल की समय पर पहचान के माध्यम से या परिणाम सफल होने पर प्रतिकृति के लिए जाते हैं।

वित्तीय क्षेत्र का अनुभव और लेखा परीक्षकों का महत्व

मुझे विश्वास है कि आप अपने नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक वित्त और सरकार की लेखा परीक्षा और लोक लेखा के विषय को समझ पा रहे होंगे। इसलिए मैं बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अन्य वित्तीय संस्थाओं में लेखा परीक्षा कार्य पर एक वित्तीय क्षेत्र विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में रिज़र्व बैंक के विशेष दृष्टिकोण साझा करना चाहूंगा।

किसी अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों की स्थिरता और वृद्धि उसके हितधारकों के बीच विश्वास पर निर्भर है। ऐसे विश्वास को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अर्थव्यवस्था के अधिक खुलेपन और प्रौद्योगिकी के आगमन की बदौलत सूचना प्रवाह के तीव्र संचरण के साथ, यह प्रणाली में विश्वसनीयता और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए सर्वोपरि हो गया है। सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर बाजार का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंकिंग उद्योग में, यह ध्यान में रखते हुए कि बैंक सार्वजनिक जमाराशियां रखते हैं, यह सार्वजनिक भूमिका वित्तीय स्थिरता के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। ऐसी सार्वजनिक भूमिका की प्रभावशीलता के लिए लेखापरीक्षा गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षक का यह कर्तव्य है कि वह बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं की लेखा परीक्षा से उत्पन्न होने वाले भौतिक महत्व के मामलों पर सीधे पर्यवेक्षक (आरबीआई) को रिपोर्ट करे। इन कारणों से बैंकों और एनबीएफसी के पर्यवेक्षक के रूप में आरबीआई की विनियमित संस्थाओं में सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीखा के तरीके में गहरी दिलचस्पी है।

इसलिए रिज़र्व बैंक का पर्यवेक्षण, विशेष रूप से अंतराल की पहचान से संबंधित आस्ति गुणवत्ता, आस्ति गुणवत्ता का मूल्यांकन और नवोन्मेषी लेखा पद्धतियों, यदि कोई हो, जो विनियमित संस्थाओं के पूंजी आधार और उनकी व्यवहार्यता पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है, से संबंधित लेखापरीक्षा गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। चल रही चिंता के रूप में। बचाव के पहले बाह्य उपाय होने के नाते, पर्यवेक्षित संस्थाओं में इसकी विफलता प्रमुख मुद्दों और जोखिमों की समय पर पहचान पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

जोखिम प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पर्यवेक्षित संस्थाओं की स्वयं की होती है; हालांकि, नियंत्रण अंतराल को पाटने और बोर्ड और निर्णय लेने वालों को आश्वासन प्रदान करने के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क की उपयुक्तता की जांच करने हेतु प्रणालीगत स्तर पर लेखापरीक्षा की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

[4] आंतरिक लेखा परीक्षक संस्थान (जनवरी 2012), पूरक मार्गदर्शन: सार्वजनिक क्षेत्र के शासन में लेखा परीक्षा की भूमिका

लेखापरीक्षा विफलताएं और संस्था/ प्रणाली पर उनका प्रभाव

सामान्यीकरण के बिना यह कहा जा सकता है कि आमतौर पर समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब स्वयं लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता से समझौता किया जाता है या लेखा परीक्षकों में अपनी भूमिका निभाने में योग्यता की कमी होती है। लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता से समझौता करने से नैतिक खतरा हो सकता है। इस प्रकार, लेखापरीक्षकों को उनके काम की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए अधिक जांच और विनियमन के अधीन किया जाता है।

लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक तथाकथित स्मार्ट लेखांकन प्रथाओं, यदि कोई हो, की जाँच करना है, जिनका प्रयोग प्रबंधन द्वारा लाभ को बढ़ा-चढ़ा कर बताने या व्यय/ देयताओं को कम करके बताने हेतु किया जाता है। मैं हमारे द्वारा अवलोकित ऐसी स्मार्ट लेखा पद्धतियों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा।

i. आईएनडी-एएस को भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों (बैंकों के अलावा), जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) शामिल हैं, के लिए लागू किया गया है जिनकी निवल मालियत ₹250 करोड़ से अधिक है। आईएनडी-एएस पिछले लेखांकन मानकों की तुलना में एक सिद्धांत-आधारित मानक है, जो अधिक निर्देशात्मक थे। आईएनडी-एएस के भीतर, आईएनडी-एएस 109 अपेक्षित ऋण हानि दृष्टिकोण के साथ प्रबंधन को अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान की आवश्यकता को निर्धारित करने में विवेक और निर्णय का प्रयोग करने की अनुमति देता है। मूल्यांकन का ऐसा लचीलापन और प्रगतिशील स्वरूप, हालांकि, 'मॉडल जोखिम' उत्पन्न करता है, यानी, मॉडल गलत धारणाओं पर भरोसा कर सकता है और वास्तविक जीवन के परिदृश्यों का प्रतिनिधित्व करने से भटक सकता है। ऐसा कई मामलों में देखा गया है। इसलिए, लेखा परीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले मॉडल का परीक्षण करें, प्रबंधन को चुनौती दें और मॉडल आउटपुट को मान्य करें।

ii. हाल ही में, 'स्वतंत्र संव्यवहार' सिद्धांत और कीमत अंतरण प्रणाली का पालन किए बिना संबंधित पक्ष के लेनदेनों के कई उदाहरण देखे गए हैं। विभिन्न माध्यमों द्वारा निधियों के विचलन और/ या संबंधित पक्षों को लाभ के अंतरण के उदाहरण हैं - अनुकूल शर्तों पर अंतःसमूह ऋण, लेनदेन के अधिक या कम बीजक बनाना, उचित मूल्यांकन के बिना आस्ति अंतरण, आदि। लेखा परीक्षकों को संबंधित या संबंधित पक्ष के लेनदेनों की जांच करने हेतु उन्हें पहचानने और पूरी तरह से जाँचने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आय या आस्तियों का कोई अनुचित हस्तांतरण नहीं हो रहा है।

iii. हमने अपारदर्शी तकनीकी साधनों (आईटी ब्लैक बॉक्स) को नियोजित करके वित्तीय विवरणों की वास्तविक प्रकृति के हेरफेर और गलत विवरण के मामले भी देखे हैं। कुछ संस्थाओं द्वारा वास्तविक लेनदेनों को आईटी समाधानों की विभिन्न परतों के नीचे छिपाया जाता है। इस प्रकार, लेखा परीक्षकों को व्यावहारिक तकनीकी ज्ञान होना चाहिए और छिपे हुए लेनदेनों की वास्तविक प्रकृति का पता लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की परतों को 'भेदने' में सक्षम होना चाहिए।

ऐसी अवांछनीय प्रथाओं और संरचनाओं को लेखापरीक्षकों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। चूंकि वित्तीय प्रणाली के पर्यवेक्षक के रूप में आरबीआई लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर होता है और लाभ उठाता है, अनुभवी लेखा परीक्षकों को उनकी रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न मंचों के माध्यम से संवेदनशील बनाया जा रहा है। हम ऑडिट की गुणवत्ता और गहन सुधार के लिए वैयक्तिक लेखा परीक्षकों, लेखा परीक्षा फर्मों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ लगातार काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में बहुत काम किया गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

सुशासन के लिए आचार संहिता

एक संबंधित मुद्दा व्यवसायों के लिए आचार संहिता का महत्व है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संस्था में हर कोई मिशन, मूल्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर स्पष्ट है। नैतिक व्यवहार कानून और विनियमों द्वारा आवश्यक न्यूनतम से कहीं अधिक होता है।

यह पहलू लेखापरीक्षा सहित विभिन्न आश्वासन तंत्रों की प्रभावकारिता और मजबूती के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। अपने कार्यों के माध्यम से नैतिक आचरण के महत्व के प्रदर्शन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। जबकि यह सभी व्यवसायों के लिए प्रासंगिक है, यह वित्तीय संस्थानों के लिए और भी महत्वपूर्ण है, जो जनता के विश्वास और जमाकर्ता की राशि को प्रत्ययी क्षमता में रखते हैं। रिज़र्व बैंक बारंबार बैंकों और एनबीएफसी में मजबूत अभिशासन फ्रेमवर्क के महत्व पर जोर देता रहा है। इस तरह के फ्रेमवर्क को पारदर्शिता, विवेकपूर्ण व्यापार कार्यनीति, प्रभावी जोखिम प्रबंधन और एक सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति के सिद्धांतों पर बनाया जाना है। वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं, लेखा परीक्षा समुदाय और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों और पर्यवेक्षकों को एक साथ काम करना होगा और एक सुदृढ़ और आत्मनिर्भर वित्तीय क्षेत्र के निर्माण के लिए सुशासन और नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे।

आधुनिक लेखा परीक्षा साधन और संबंधित मुद्दों को अपनाना

इस डिजिटल युग में, वित्तीय लेखांकन और इसके समेकन के तरीके में बड़े परिवर्तन हुए हैं। लेखा-परीक्षा का पेशा तकनीक को अपनाने में पिछड़ नहीं सकता। नई तकनीकों के निरंतर उन्नयन और एकीकरण के माध्यम से कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स एंड टेक्निक्स (सीएएटीटी) जैसे तकनीकी उपकरणों को अपनाने से लेखा परीक्षा में काफी दक्षता आएगी। समानांतर में, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि लेखा परीक्षा के लिए ऐसे तकनीकी साधनों को अपनाना पेशेवर निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए, लेखापरीक्षा में प्रौद्योगिकी उपकरणों को एकीकृत करते समय हमेशा एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।

आरबीआई की पर्यवेक्षित संस्थाओं की लेखापरीक्षा

अब मैं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी पर्यवेक्षित संस्थाओं में लेखापरीक्षा कार्य में सुधार लाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए कुछ कदमों पर आता हूं।

(i) रिज़र्व बैंक स्पष्ट है कि वित्तीय स्थिरता, अन्य बातों के अलावा, बाजार के विश्वास पर निर्भर करती है जो निवेशक / हितधारक के विश्वास से उपजा है। यह बदले में, वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता से प्रभावित होता है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपने वित्तीय विवरणों में सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का पूर्ण और निष्पक्ष प्रकटीकरण करें। आरबीआई द्वारा कुछ अनिवार्य प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

- नियामक पूंजी की संरचना का विवरण ताकि हितधारक पूंजी की गुणवत्ता को समझ सकें;
- अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में संचलन के साथ-साथ अग्रिमों की गुणवत्ता का विवरण उन पर धारित प्रावधानों के साथ;
- लंबित शिकायतों का विवरण, शिकायतों के प्रमुख आधार और उनका निपटान।

(ii) सितंबर 2020 में, आरबीआई ने लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) के लिए प्रारूप को संशोधित किया था ताकि बैंकिंग पर्यवेक्षण (बीसीबीएस) पर बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन (बीसीबीएस) दस्तावेज़ में "बैंकों की बाहरी लेखा परीक्षा" में बताई गई विवेकपूर्ण पर्यवेक्षी आवश्यकताओं के कवरेज को बढ़ाकर इसके उपयोगिता को बढ़ाया जा सके।

(iii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) प्रणाली, जिसे 2002 में शुरू किया गया था और जनवरी 2021 में और मजबूत किया गया था। इसके बाद बड़े एनबीएफसी और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए फरवरी 2021 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिसमें ऐसी संस्थाओं के लिए व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए धीरे-धीरे आरबीआईए प्रणाली की ओर बढ़ने के बारे में ज़िक्र था।

(iv) अप्रैल 2021 में, आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और एनबीएफसी में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देशों को अद्यतन किया है, जो लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने, लेखा परीक्षक नियुक्तियों में हितों के टकराव से बचने और और लेखापरीक्षा के मानक और गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वामित्व-तटस्थ लेखा परीक्षा नियमों को लागू करते हैं।

आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी में संचालन और जोखिम प्रबंधन में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें अप्रैल 2021 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में कॉर्पोरेट प्रशासन पर अद्यतन दिशानिर्देश जारी करना शामिल है। एससीबी में मुख्य जोखिम अधिकारियों (सीआरओ) की भूमिका को मजबूत किया गया है और बड़े एनबीएफसी और यूसीबी में सीआरओ की आवश्यकता अनिवार्य कर दी गई है। कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) से संबंधित तपन रे समिति की सिफारिशों को लागू करके जटिल समूह संरचनाओं को सरल बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। 22 अक्टूबर, 2021 को एनबीएफसी के पैमाने पर आधारित विनियमन के लिए एक फ्रेमवर्क की घोषणा की गई है।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण और वित्तीय प्रणाली की बढ़ती जटिलता के साथ, एक ठोस, स्थिर और जीवंत वित्तीय प्रणाली के लिए और लोगों के भलाई के लिए लेखा परीक्षा महत्वपूर्ण हो गई है। लेखापरीक्षकों को निरंतर आधार पर कौशल को अद्यतन और उन्नत करने और अपने कार्य को सबसे प्रभावी तरीके से करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में लेखा परीक्षक की प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण लेकिन रचनात्मक चुनौती देने वाली होगी, जिसमें सार्वजनिक हित और लेखा परीक्षा की गुणवत्ता पर स्पष्ट ध्यान दिया जाएगा। संक्षेप में, और भी अधिक पेशेवर, योग्य, निष्पक्ष, सिद्धांत संचालित, नैतिकता और जागरूकता और दूरदर्शिता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।

मुझे विश्वास है कि आप सभी सिविल सेवा और सीएजी की संस्था की सर्वोच्च विरासत के मशाल वाहक के रूप में कार्य करेंगे और राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तथा लेखा अकादमी की - लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा (जनहित के लिए सत्य के प्रति वचनबद्धता) के लक्ष्य को आत्मसात करके जवाबदेही, पारदर्शिता, अखंडता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखेंगे जो एक अच्छे लोक सेवक की आवश्यक विशेषताएं हैं।

इसके साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सभी के लिए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में अच्छे भविष्य की कामना करता हूं।